पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

जीतेन्द्र कुमार चौरसिया

बनाम

बिहार राज्य

2023 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 2955

13-08-2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्रशेखर झा, न्यायाधीश)

विचार के लिए मुद्दा

क्या महिला थाना कांड संख्या 50/2021 से उत्पन्न ट्र. संख्या 142/2023 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VI-सह विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं सजा का निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 376—लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012—धारा 4—बलात्कार—पीड़िता विवाह समारोह में शामिल होने गई थी, जहां अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ बलात्कार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी-पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में तभी बताया जब बलात्कार/घटना का वीडियो वायरल कर दिया गया—एफआईआर दर्ज करने में देरी अपीलकर्ता द्वारा दी गई धमकी के कारण हुई।

निर्णीत: पीड़िता "उत्कृष्ट गवाह" के परीक्षण में खरा नहीं उतरी—परिसर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी के अवसर पर पीड़िता और उसके पिता को कोई भी निमंत्रण देने से इनकार कर दिया—दोषसिद्धि का विवादित फैसला और सजा का आदेश रद्द कर दिया गया और अलग रखा गया—अपील स्वीकार की गई।

(पैराग्राफ 14, 17, 33 से 35)

न्याय दृष्टान्त

रविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2022) 7 एससीसी 581—पर भरोसा किया गया; संतोष प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (2020) 3 एससीसी 443; जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2013) 7 एससीसी 263—संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

मुख्य शब्दों की सूची

बलात्कार; पीड़िता; उत्कृष्ट गवाह।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VI-सह विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा महिला थाना कांड संख्या 50/2021 से उत्पन्न ट्र. संख्या 142/2023, आर.एन. 22/2022 में दोषसिद्धि के निर्णय एवं सजा के आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री योगेश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुश्री कुमारी अनुपम, अधिवक्ता, श्री विकास कुमार झा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: अनीता कुमारी सिंह, एपीपी।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की आपराधिक अपील **(ए.न्या.) सं.2955**

थाना कांड संख्या -50 वर्ष-2021 थाना-महिला थाना, जिला-समस्तीपुर से उत्पन्न

==========

जितेंद्र कुमार चौरसिया, पिता- राम प्रवेश चौरसिया, निवासी-ग्राम -साहित, थाना.-विद्यापतिनगर, जिला- समस्तीपुर

... ... अपीलकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

उपस्थितिः

अपीलकर्ता के लिए : श्री योगेश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
सुश्री कुमारी अनुपम, अधिवक्ता
श्री विकाश कुमार झा

उत्तरदाता-राज्य के लिए: श्रीमती अनीता कुमारी सिंह, स.लो.अ.

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः13-08-2024

यह अपील अपीलकर्ता /दोषी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता(जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 374 (2)के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। इसमें विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VI-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 01.05.2023 को दिए गए दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 16.05.2023 को पारित सजा के आदेश को चुनौती दी गई है। यह आदेश महिला पुलिस कांड संख्या 50/2021 से 2023 का वि.सं.142, 2023 का आर.एन. 22 में दिया गया था,जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता /दोषी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (संक्षिप्त में 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 4 के तहत दंडनीय

अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उसके तहत दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास से गुजरना होगा ।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, सूचक /पीड़िता (अ.सा -1) की लिखित जानकारी के माध्यम से उपलब्ध है, जो कि प्राथमिकी का आधार है कि दिनांक 30.05.2021 पर वह एक प्रियंका कुमारी के विवाह समारोह में भाग लेने गई थी। लगभग 1 बजे, विवाह स्थल पर एक काजल देवी ने उसे छत से मोबाइल फोन लाने के लिए कहा, जितेंद्र कुमार चौरसिया (अपीलकर्ता) के साथ एक साजिश के तहत, जो पहले से ही छत पर उसका इंतजार कर रहा था और जब वह वहाँ गई, तो उसने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने कहा कि वह अपने पिता को घटना बताएगी, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उसी समय, एक अन्य सह-अभियुक्त, सूरज कुमार ने पूरी घटना का एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। जब सूचना देने वाले/पीड़िता के पिता ने दिनांक 15.07.2021 को वह वीडियो देखा, तो वह शिकायत करने के लिए जितेंद्र कुमार चौरसिया (अपीलकर्ता) के घर गए, जहाँ जितेंद्र कुमार चौरसिया (अपीलकर्ता), राम प्रवेश चौरसिया, सावित्री देवी, गुड़िया कुमारी और विवेक कुमार ने उसे गाली देना शुरू कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी।

3. उपरोक्त तथ्यात्मक आरोप के साथ, सूचक /अ.सा-1 ने एस. एच. ओ., महिला पुलिस थाना,समस्तीपुर से अपीलकर्ता/दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

4.सूचक/अ.सा.-1 की उपरोक्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने भारतीय दंड विधान (संक्षेप में 'भा.दं.वि.') की धारा 376, 506, 420, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम (संक्षेप में 'आईटी अधिनियम') की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 18.07.2021 को महिला थाना काण्ड संख्या 50/2021 दर्ज किया, जिसमें आरोपी/अपीलकर्ता जितेंद्र कुमार @जितेंद्र कुमार चौरसिया और अन्य सह-आरोपी सूरज कुमार को शामिल किया गया।

5. जाँच पूरा होने के उपरांत और जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, इस मामले के अनुसंधान कर्ता ने भा.दं.वि. की धारा 376,506,420 सहपठित धारा 34, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 अधिनियम, 2012 और आयकर अधिनियम की धारा 67-ए और 67-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 207 के तहत पुलिस कागजात की आपूर्ति करने के बाद अपीलकर्ता -दोषी के खिलाफ भा.दं.वि. की धारा 376 (3), 506, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और आई. टी. अधिनियम की धारा 67-बी के तहत भी आरोप तय किए, जिन्हें अपीलकर्ता /दोषी को समझाया गया था, जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

6. अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों से पूछताछ की है। वे इस प्रकार हैंः-(i) **अ.सा-1 सूचक /पीड़िता**; (ii) **अ.सा-2 पीड़िता का पिता;** (iii) **अ.सा-3 पीड़िता की माँ;** (iv) **अ.सा-4 डॉ. गिरीश कुमार,** जिन्होंने पीड़िता से पूछताछ की है**; (v) अ.सा-5 पुष्पलता कुमारी,** इस मामले अनुसन्धान कर्ता; **(vi) अ.सा-6 पंकज कुमार**; और

(vii) **अ.सा-7 शिव प्रसाद चौरसिया**, घर का मालिक, जहाँ कथित घटना हुई थी।

7. मौखिक साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित प्रदर्शों /दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी भरोसा किया है, जो हैंः

क्रम. सं.	प्रदर्शों की संख्या	प्रदर्श दस्तावेजों के नाम
1.	प्रदर्श-पी-1	एफ.आई.आर. पर सूचक-सह-पीड़िता के हस्ताक्षर।
2.	प्रदर्श-पी-2	धारा 164 दं.प्र.सं.के तहत पीड़िता के बयान पर उसके हस्ताक्षर।
3.	प्रदर्श -पी-3	चिकित्सा अनुरोध पर पीड़ित के हस्ताक्षर।
4.	प्रदर्श-पी-4	चिकित्सकीय अनुरोध पर चिकित्सक के हस्ताक्षर।
5.	प्रदर्श-पी-5	प्राथमिकी पर एस. एच. ओ. के हस्ताक्षर।
6.	प्रदर्श-पी-6	आरोपपत्र ।
7.	प्रदर्श-पी-7	पूरक आरोप पत्र।
8.	प्रदर्श-पी-8	पीड़ित की उम्र के समर्थन में प्रवेश पत्र।
9.	प्रदर्श-2 एबं 2 /1	चिकित्सा प्रतिवेदन और डॉक्टर के हस्ताक्षर
10.	प्रदर्श-3	सूचक /पीड़ित का लिखित आवेदन।
11.	प्रदर्श-4	औपचारिक प्राथमिकी

8. मुकदमे के दौरान सामने आए सबूतों/परिस्थितियों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता/आरोपी की जांच की है, जिसमें उसने मुकदमे के दौरान सामने आए सभी सबूतों का पूरी तरह से खंडन किया है और अपनी पूरी बेगुनाही और गलत निहितार्थ का दावा किया है।

9. मुक़दमे के दौरान सामने आए साक्ष्यों **पर** विचारण और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद, विद्वान विचारण

न्यायालय ने अपीलकर्ता /दोषी/अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उसे ऊपर बताए गए तरीके से सजा सुनाई है।

10. दोषसिद्धि की सजा के आदेश के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता /दोषी ने वर्तमान अपील को दायर किया है।

11. इसलिए, वर्तमान अपील।

<u>अपीलकर्ता की ओर से तर्कः</u>

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री योगेश चंद्र वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि का निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत है, जहां अभियोजन पक्ष के कई प्रमुख विरोधाभासों और खामियों की अनदेखी की गई थी और केवल पेन-ड्राइव सामग्री के आधार पर, जो एक द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि भा.द.वि. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत सुरक्षित की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि विवाद की पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता का निहितार्थ गलत था, जहाँ पीड़िता को वर्तमान मामला दर्ज करने के लिए साधन बनाया गया था। इस तथ्य को घर के मालिक के बयान से आसानी से एकत्र किया जा सकता है, जहां विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसने कथित तिथि यानी दिनांक 30.05.2021 को किसी भी घटना से इनकार किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में डेढ़ महीने की देरी से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता के बयान में बड़ी विसंगतियां हैं, क्योंकि उसने प्राथमिकी में अलग-अलग विवरण दिए, दं.प्र.सं.की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में और मुकदमे के दौरान अ.सा.-1 के रूप में भी और उसके सभी बयानों को

सामूहिक रूप से ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि वह "उत्कृष्ट गवाह" की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में विफल रही। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़िता की चिकित्सा जांच से कुछ भी सामने नहीं आता है, जिससे यह पता चल सकता है कि उस पर यौन हमला किया गया था और इसके अलावा वह अपनी रेडियोलॉजिकल जांच के अनुसार साढ़े 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बीच पाई गई थी और यदि प्लस (+) माइनस (-) दो वर्ष का लाभ दिया जाता है, तो उसे घटना की तारीख को वयस्क कहा जा सकता है और इसलिए, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दर्ज दोषसिद्धि भी संदिग्ध प्रतीत होती है। यह भी बताया गया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 या भा.दं.वि. की धारा 376 के तहत दोषी ठहराने के लिए प्रवेश आवश्यक कानूनी घटक है, लेकिन अभियोजन पक्ष पीड़िता के बयान से यह स्थापित करने में विफल रहा कि क्या कोई यौन प्रवेश विशेष रूप से उस पृष्ठभूमि में किया गया था, जब पीड़िता **"उत्कृष्ट गवाह"** के परीक्षण में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकी थी। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी प्रतिवेदन पर भरोसा किया जो इसके माध्यम से उपलब्ध है। **संतोष प्रसाद बनाम बिहार राज्य [(2020) 3 एससीसी 443]।**

13. श्री वर्मा ने आगे कहा कि पेन ड्राइव और फेसबुक सामग्री, जो अपीलकर्ता के निहितार्थ का एकमात्र आधार है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के संदर्भ में साबित नहीं हुआ था और इसलिए, दोषसिद्धि, जो केवल उक्त आधार पर प्राप्त की गई थी, कानून की दृष्टि से पूरी तरह से खराब है और जिसका लाभ अभियुक्त/अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी

प्रतिवेदन पर भरोसा किया जो की **रविन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2022) 7 एससीसी 581]** के माध्यम से उपलब्ध है। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई कि *अपीलकर्ता* को दोषी ठहराने के विवादित फैसले को रद्द और अपास्त कर दिया जाए।

13.1. तर्क का समापन करते हुए, श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि विचारण न्यायालय अपने विवादित फैसले के माध्यम से आश्वस्त प्रतीत होती है कि वह वीडियो या पेन-ड्राइव पर भरोसा नहीं करेगी, जिसे अदालत के समक्ष पेश किया गया था, लेकिन उसने अपीलकर्ता के बयान पर भरोसा किया जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था, जिसे उसे उसी पेन-ड्राइव को विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश के कक्ष में दिखाने के बाद दर्ज किया गया था, जिसे सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपीलकर्ता का बयान, जो वीडियो सामग्री के आधार पर दर्ज किया गया था, अपीलकर्ता की ओर से किसी भी स्पष्ट कार्य का सुझाव नहीं देता है और केवल एक वीडियो में एक साथ उपस्थिति के आधार पर, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि पूरी तरह से विकृत है और इसलिए, अकेले इसी आधार पर, दोषसिद्धि के फैसले को रद्द किया जा सकता है और दरकिनार किया जा सकता है।

<u>राज्य की ओर से तर्कः</u>

14. *इसके विपरीत,* इसके विपरीत,राज्य की ओर से बहस करते हुए विद्वान स.लो.अ. ने प्रस्तुत किया गया कि विचारण के दौरान, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी पीड़िता का मूल प्रवेश पत्र **प्रदर्श-पी/8** के रूप में

प्रदर्शित किया गया था, जिसमें उसकी जन्म तिथि 18.06.2006 के रूप में दिखाई गई है और इसलिए, वह घटना की तारीख को नाबालिग थी, जो कथित तौर पर 30.05.2021 पर हुई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़िता को बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर मुकदमे के दौरान पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अर्थ के भीतर विधिवत "बच्चा" साबित किया गया था, जो किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 94(2) के अनुसार विचाराधीन अपराध के पीड़ित की जन्मतिथि ज्ञात करने के लिए एक परिभाषित दस्तावेज है, जिसे **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य [(2013) 7 एससीसी 263]** के माध्यम से उपलब्ध कानूनी अनुपात द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना का खुलासा पीड़िता द्वारा अपने माता-पिता को केवल तभी किया गया था जब घटना का वीडियो वायरल किया गया था, *वास्तव में* आरोप को कम नहीं करता है, क्योंकि यह पीड़ित के बयान से पूरी तरह से पुष्ट प्रतीत हो रहा है। यह भी इंगित गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी धमकी के कारण हुई थी यह भी बताया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी धमकी के कारण हुई थी और इस संबंध में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया।

15. मैंने विचारण न्यायालय दस्ताबेजों को ध्यान से देखा है और दस्ताबेज पर उपलब्ध सबूतों को देखा है और साथ ही पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर भी विचार किया है।

16. दलीलें सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्यों पर चर्चा की

आवश्यकता है ताकि वर्तमान अपील के न्यायोचित और उचित निपटान के लिए उनका पुनर्मूल्यांकन किया जा सके।

17. इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण गवाह अ.सा. है, जो खुद पीड़िता है। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में दोषसिद्धि केवल उसकी एकमात्र गवाही पर ही प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा यह कहा गया था कि वह प्रियंका कुमारी के विवाह समारोह में भाग लेने गई थीं, जिसे उनके आवास पर संपन्न हुआ था, जहां अपीलकर्ता द्वारा उन पर बलात्कार की वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया था। यह कहा गया कि अपीलकर्ता घटना से पहले से ही उसे जानता था, लेकिन वे आपस में बातचीत नहीं करते थे। उसने गवाही दी कि दिनांक 30.05.2021 को रात लगभग 11.30 बजे एक काजल कुमारी ने उसे घर की छत से अपना मोबाइल फोन लाने को कहा, जो अपीलकर्ता की चचेरी भाभी है। उपरोक्त अनुरोध के अनुपालन में, वह छत तक गई, जहाँ अपीलकर्ता पहले से ही मौजूद था और उसने वहाँ उसके साथ बलात्कार किया। उक्त स्थान मारवा (शादी की मंडप/कुटिआ) के पीछे था। वहाँ कोई नहीं था। वह चिल्लाई, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। कहा गया था कि शादी समारोह के तेज संगीत के कारण किसी ने उनका रोना/क्रंदन नहीं सुना। इसके बाद, अपीलकर्ता ने घटना का खुलासा नहीं करने की धमकी दी, क्योंकि वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो देगी और उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई। उसने गवाही दी कि पारिवारिक प्रतिष्ठा और सामाजिक कलंक के डर से उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ समय बाद, जब उसके पिता गाँव की विदाई समारोह (भोज) में भाग लेने जा रहे थे, तो सह-ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उसकी बेटी के साथ हुई घटना के बारे में कुछ वीडियो वायरल हो गया और

उसके बाद, वीडियो उसके पिता को दिखाया गया। घर लौटने के बाद, जब उसके पिता ने घटना के बारे में पूछा, तो वह रोने लगी और अपने पिता को घटना के बारे में विस्तार से बताया, जिसके बाद उसके पिता आरोपी/अपीलकर्ता जितेंद्र कुमार चौरसिया के घर गए, जहाँ उसके माता-पिता ने उस पर हमला किया। उनके साथ उनके पिता भी थे। उसने मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता /दोषी की पहचान की, जो नीली टी-शर्ट में था और कहा कि यह वह व्यक्ति है, जिसने उसके साथ बलात्कार किया और दूसरा व्यक्ति सूरज कुमार है, जिसने वीडियो वायरल किया। उन्होंने लिखित जानकारी पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जो टाइप की हुई प्रति है, जो उसे उसके बयान के अनुसार टाइप की हुई मिली, जिसे उसकी पहचान के बाद प्रदर्श-**पी-1/अ.सा.-1** के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान पर हस्ताक्षर की भी पहचान की, जो उनकी पहचान पर प्रदर्श-'**पी-2/अ.सा.-1**' के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने चिकित्सा जांच के लिए अपनी सहमति भी दी, जहां उन्होंने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जो उनकी पहचान पर प्रदर्श-'**पी-3/अ.सा.-1**' के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

17.1 प्रति परीक्षण के बाद, उनके द्वारा यह कहा गया कि वर्तमान मामला घटना के डेढ़ महीने बाद दर्ज किया गया था। यह कहा गया था कि शिव प्रसाद चौरसिया घर के मालिक थे। उसने कहा कि वह घटना का गवाह नहीं है। काजल देवी उक्त शिव प्रसाद चौरसिया के भाई की बहू हैं। वह भी उक्त घटना की गवाह नहीं है। यह कहा गया था कि उन्हें लिखित रूप में कोई निमंत्रण नहीं मिला था, बल्कि यह शादी की पार्टी/समारोह में शामिल होने के लिए मौखिक निमंत्रण था। उसने कहा कि उसके कपड़ों पर घटना का कोई सबूत नहीं था और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं लगी थी। उन्होंने स्पष्ट

रूप से कहा कि जब शारीरिक संबंध स्थापित किया गया था, तो वह होश में थी और वह शारीरिक संबंध के बाद भी होश में थी। यह कहा गया था कि यह घटना *'जयमाला'* के समय हुई थी। वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी छत पर नहीं था। उसने कहा कि उसके पिता भी शादी में शामिल हुए थे लेकिन वह अपने दोस्त के साथ वहाँ गई थी। वह भी अपने घर अकेली लौट आई। उसने पुलिस को अपने कपड़े नहीं दिए, जो घटना की तारीख और समय पर पहने हुए थे। यह कहा गया था कि छत सीमा से घिरी नहीं थी। यह कहा गया था कि बलात्कार खड़े होकर किया गया था। उसने यह भी कहा कि घर का मालिक अपीलकर्ता का रिश्तेदार था और इसलिए उसे भी आमंत्रित किया गया था। विशिष्ट प्रश्न पर कि लगभग डेढ़ महीने वह मूक क्यों रहती है, यह जवाब दिया गया कि विलंब अभियुक्त/अपीलकर्ता के कारण हुआ । उसने कहा कि घर की छत पर रोशनी उपलब्ध थी, लेकिन शादी से संबंधित कोई समारोह नहीं था। वह वहाँ लगभग 1 से 2 घंटे तक रहती है। वह 'जयमाला समारोह' में शामिल नहीं हुईं, क्योंकि यह घटना उसी समय हुई थी। यह कहा गया था कि उसकी तस्वीर वीडियोग्राफी में उपलब्ध नहीं है, जो शादी के अवसर पर की गई थी। उसने घर की सीमा का खुलासा किया, जहाँ उसने कहा कि पश्चिम की ओर का घर सह-आरोपी सूरज का है। उसने कहा कि घर की छत पर उसके और जितेंद्र के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। उसने इस बात से इनकार किया कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और उसने अपीलकर्ता को पिछली दुश्मनी के कारण फंसाया था।

18. **अ.सा.-2** पीड़िता का पिता है, जिसने गवाही दी कि दिनांक 15.07.2021 को जब वह गाँव में एक भोज समारोह में शामिल होने गया था, तो उसे सह-ग्रामीणों से घटना के बारे में पता चला कि घटना से संबंधित एक

वीडियो वायरल हो गया है। उसने कहा कि उसने उक्त वीडियो में अपीलकर्ता को उसकी बेटी के साथ बलात्कार करते और उसके कपड़े पकड़कर खींचते हुए देखा। उक्त वीडियो में कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके बाद, उसने घटना के बारे में उसकी पत्नी (अ.सा.-3) को बताया, जिसने पीड़िता से पूछा, इसके बाद, घटना के बारे में उन्हें बताया गया और उसके बाद, वर्तमान मामला दर्ज किया गया। उन्होंने अपीलकर्ता की पहचान की और कहा कि वह वही व्यक्ति है जो वीडियो में उसकी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था और एक अन्य आरोपी सूरज कुमार है, जिसने वीडियो वायरल किया था।

18.1. प्रतिपरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि उनका पूरा बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह अपने मामले के समर्थन में शिव प्रसाद चौरसिया को गवाह के रूप में बुलाएंगे। यह बयान दिया गया कि पीड़िता घटना के समय दसवीं कक्षा की परीक्षार्थी थी। यह कहा गया था कि शादी की पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मौखिक था। उन्होंने बताया कि घटना दिनांक 30.05.2021 को रात्रि 11.30 बजे घटी, जैसा कि उनकी बेटी/पीड़िता ने बताया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पुलिस के सामने बयान नहीं दिया कि उन्हें पीड़ित से ही दिनांक 15.07.2021 को घटना के बारे में पता चला था। यह कहा गया था कि वायरल वीडियो की क्लिप अदालत के समक्ष पेश करने के लिए उसके साथ सुरक्षित हिरासत में है। उन्होंने कहा कि डेढ़ महीने के बाद मामला दर्ज किया गया था और यह केवल वायरल वीडियो के कारण दर्ज किया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि शिव प्रसाद चौरसिया के घर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

19. अ.सा.-3 पीड़िता की माँ, अर्थात् कामिनी देवी, है। उसने भी उसी तर्ज पर गवाही दी जिस तर्ज पर **अ.सा**-2 ने गवाही दी थी। उसने वीडियो देखने का भी दावा किया, जहाँ उसने अपीलकर्ता को अपनी बेटी के साथ बलात्कार करते हुए पाया। यह कहा गया था कि यह सूरज कुमार था, जो वीडियो बना रहा था। उसने कहा कि वह इस घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है। यह कहा गया था कि भोज (विदाई पार्टी) दिनांक 15.07.2021 पर श्याम चौरसिया/सह-ग्रामीण के आवास पर था और उसके बाद, वे सीधे विद्यापीठ पुलिस थाना गए। उसने कहा कि घर का मालिक इस मामले का गवाह नहीं है।

20. अ.सा.-4 डॉ. गिरीश कुमार हैं जो दिनांक 19.07.2021 को उप चिकित्सा अधीक्षक, सदर अस्पताल, समस्तीपुर के पद पर तैनात थे । उन्होंने बताया कि उसी दिन, उनकी अध्यक्षता में डॉ. डी.के. शर्मा, डॉ. मेघा आहूजा और डॉ. जुनैद अख्तर के साथ पीड़िता की जाँच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था,जाँच के उपरांत निम्नलिखित चोटें पाई गईं, जो इस प्रकार हैं:-

"एम. आई.-ऊपरी ओठ पर काला तिल
ऊंचाई-4 फीट 11 इंच
वजन-28 किग्रा। दाँत-7 x 7/7 x 7
एलएमपी-29-06.2021

<u>सामान्य परीक्षा</u>

(i) शरीर और गुप्तांगों पर कोई चोट और बाहरी शरीर नहीं देखा गया है।

((ii) सहायक और सार्वजनिक बाल विकसित
(iii) स्तन विकसित।

<u>पी/ए परीक्षा</u>

पेट-नरम

पी/वी-योनिच्छद पुराना, ठीक हो चुका और फटा हुआ।

सूक्ष्म परीक्षण के लिए भेजे गए दो स्लाइड योनि स्वाब-रिपोर्टों से पता चलता है कि कोई शुक्राणु नहीं मिला है।

निजी अंगों पर कोई चोट या विदेशी वस्तु नहीं दिखी।

<u>जाँच-पड़ताल</u>

एक्स-रे पेल्विस एपिव्यू से पता चलता है कि दोनों इलियाक शिखाओं का एपिफ़ाइसिस पूरी तरह से दिखाई दिया, लेकिन जुड़ा नहीं।

कोहनी के जोड़ का एक्स-रे - कोहनी के जोड़ का एपिफ़ाइसिस पूरी तरह से जुड़ा हुआ दिखाता है।

कलाई के जोड़ का एक्स-रे - रेडियस और अल्ना के डिजिटल सिरे का एपिफ़ाइसिस पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है।

19.07.2021 को यूपीटी-नकारात्मक।

यूएसजी-सामान्य स्कैन। "

20.1. उन्होंने उपरोक्त शारीरिक और रेडियोलॉजिकल निष्कर्षों के आधार पर पीड़िता की आयु 15½ -16½ वर्ष के बीच होने की राय दी। उन्होंने आगे कहा कि जाँच के समय यौन उत्पीड़न का कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ-साथ डॉ. मेघा आहूजा, डॉ. डी.के. शर्मा और डॉ. जुनैद के लेखन की पहचान की, जिसे उनकी पहचान के बाद **प्रदर्श-पी-3/अ.सा.-4** के रूप में प्रदर्शित किया गया।

21. **पीडब्लू-5 पुष्पलता कुमारी हैं,** जो इस मामले की अनुसन्धानकर्ता हैं। उसने प्राथमिकी /लिखित जानकारी पर अपने हस्त-लेखन और हस्ताक्षर की पहचान की, जो उसे पीड़ित द्वारा 18.07.2021 को दिया गया था। उसने स्वयं जाँच शुरू की और उसकी पहचान, लिखित जानकारी और उसके हस्ताक्षर के आधार पर उसे **प्रदर्श-पी-5/अ.सा.-5** के रूप में चिह्नित

किया गया। यह कहा गया था कि औपचारिक प्राथमिकी तीन पृष्ठों में चलती है और उसकी पहचान पर, औपचारिक प्राथमिकी के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमशः **प्रदर्श-पी-5/1/अ.सा.-5, पी-5/2/अ.सा.-5 और पी5/3/अ.सा.-5** के रूप में प्रदर्शित किया गया। पीड़िता के बयान के अनुसार उसने घटना स्थल का दौरा किया। उसने पीड़िता को दं.प्र.सं.की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश किया। उसने पीड़िता की चिकित्सा जाँच भी कराइ। जाँच के दौरान, उसने गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए कहा और अनुसंधान समाप्त करने के उपरांत , इस मामले को सही पाते हुए, 2021 का आरोप-पत्र संख्या 1 दिनांक 14.09.2021 को प्रस्तुत किया, जहाँ उसने अपने हस्ताक्षर और हस्त-लेखन की पहचान की, जो उसकी पहचान पर **पी-6/अ.सा.-5** के रूप में प्रदर्शित हुआ। इस अपीलकर्ता के विरुद्ध एक पूरक आरोप-पत्र संख्या 2/2022 दिनांक 08.01.2022 भी प्रस्तुत किया गया था।

21.2. प्रतिपरीक्षण के बाद, उसने कहा कि घटना के लगभग दो महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह कहा गया कि चिकित्सा जांच में, पीड़ित को टूटे हुए हाइमेन के साथ पाया गया, इसलिए उसने भा.दं.वि. की धारा 376 के तहत वर्तमान मामला दर्ज किया। उसने कपड़े जैसा कुछ भी जब्त नहीं किया, जो घटना की तारीख और समय पर पीड़िता द्वारा पहना गया था और घटना के लिए कोई प्रासंगिक परिस्थितिजन्य सबूत भी नहीं मिला। उसने आरोपी/अपीलकर्ता से कोई वीडियो और मोबाइल जब्त नहीं किया। उसने अपीलकर्ता /अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया। उन्होंने घर की मालिक प्रियंका कुमारी और शिव प्रसाद चौरसिया का बयान दर्ज नहीं किया। उसने काजल देवी का बयान भी दर्ज नहीं किया, जो अपीलकर्ता की भाभी *(साली)* है, जिसने पीड़ित को अपना मोबाइल फोन छत से लाने के लिए कहा

था। उसने पीड़िता की उम्र से संबंधित कोई प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था। उसने इस तथ्य के समर्थन में कोई सबूत एकत्र नहीं किया कि घटना की तारीख को पीड़िता नाबालिग थी। उन्होंने विवाह समारोह के समर्थन में कोई विवाह कार्ड जब्त नहीं किया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह यह कहने में असमर्थ है कि किस मोबाइल, पेन ड्राइव से तैयार किया गया था, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है और इस तथ्य का खुलासा केवल पीड़िता ही कर सकती है। जाँच के दौरान उसने पेन ड्राइव का सत्यापन नहीं किया है। जाँच के दौरान उसने कोई पेन-ड्राइव जब्त भी नहीं की। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि उनकी जांच अवैज्ञानिक और दोषपूर्ण है। उसने सह-आरोपी सूरज का मोबाइल भी जब्त नहीं किया।

22. **अ.सा.-6 पंकज कुमार हैं,** जो पीड़िता का सह-ग्रामीण प्रतीत होता है और घटना का सुना हुआ गवाह प्रतीत होता है और उसका साक्ष्य वर्तमान घटना पर चर्चा करने के लिए इतना प्रासंगिक नहीं है। सह-ग्रामीण होने के कारण उसने सुनी-सुनाई सूचना के आधार पर घटना का समर्थन किया ।

23. **अ.सा. -7 शिव प्रसाद चौरसिया** हैं, घर का मालिक, जहाँ कथित घटना दिनांक 30.05.2021 पर घटित हुई थी। यह कहा गया था की कि जाँच के दौरान उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था और इसलिए, उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग करके बुलाया गया था। अ.सा.-2, पीड़ित का पिता भी उसे गवाह के रूप में बुलाना चाहता था। जांच करने पर, वह अपने बयान से पलट गया, लेकिन उसने विवाह समारोह के तथ्य का समर्थन किया, जो दिनांक 30.05.2021 को उसकी बेटी अर्थात,प्रियंका कुमारी की शादी के लिए आयोजित किया गया था।

यह कहा गया था कि जितेंद्र कुमार ने उस तारीख को उसके घर पर कुछ नहीं किया था और यह पूरी तरह से झूठा मामला है। उन्होंने कहा कि मामला दुश्मनी के कारण दर्ज किया गया था और शादी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

23.1. प्रतिपरीक्षण के बाद, यह कहा गया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के अवसर पर लालचुन चौरसिया यानी अ.सा.-2/पीड़िता के पिता और उनके परिवार को आमंत्रित नहीं किया था। यह कहा गया था कि सह-ग्रामीण शादी में शामिल हुए थे और उनके घर में तथाकथित तिथि और समय पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

24. उपरोक्त गवाहों की चर्चा से यह प्रतीत होता है कि इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं पीड़िता है, जिससे अ.सा. -1 के रूप में चिन्हित की गई थी। उनकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। उसकी उम्र और जन्मतिथि **प्रदर्श-पी/8** के माध्यम से सिद्ध की गई, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी उसका प्रवेश पत्र है और उसे अभिलेख में दर्ज किया गया और दं.सं.प्र. की धारा 294 के तहत साक्ष्य के रूप में पढ़ा गया क्योंकि आरोपी/अपीलकर्ता ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई थी। बाकी गवाह घटना के कथित गवाह हैं, जिनमें पीड़िता /अ.सा.-1 और अ.सा.-2 के माता-पिता भी शामिल हैं।

25. एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो वर्तमान मामले में उत्पन्न होता है, यह तय करना है कि क्या पीड़ित का बयान इतना विश्वसनीय और भरोसेमंद है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने संबंधित अपराध के मूलभूत पहलू को स्थापित किया है ताकि POCSO

अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत उपलब्ध अनुमान को लागू किया जा सके।

26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़िता (अ.सा.-1) ने विशेष रूप से बयान दिया कि अपीलकर्ता ने दिनांक 30.05. 2025 को प्रियंका कुमारी के विवाह समारोह में उसके साथ बलात्कार किया था। '*जयमाला*' समारोह के समय वह उनकी '*भाभी*' काजल देवी का फोन लेने के लिए छत पर गई थीं। कहा गया कि काजल देवी से न तो जाँच के दौरान पूछताछ की गई और न ही मुकदमे के दौरान। यह कहा गया था कि घटना के दौरान कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था और यह खड़े होने की स्थिति में हुआ था। यह भी स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान घटना का मामला घटना के डेढ़ महीने बाद दर्ज किया गया था, जब घटना का वीडियो वायरल किया गया था और यह अ.सा.-2 के संज्ञान में आया, जो पीड़िता का पिता है। उक्त वीडियो की क्लिप कभी भी अनुसंधान कर्ता को नहीं सौंपी गई। जाँच के दौरान अनुसन्धान कर्ता /अ.सा.-5 द्वारा पेन-ड्राइव को जब्त नहीं किया गया था। पेन-ड्राइव के वीडियो की प्रामाणिकता को साबित नहीं कहा जा सकता है, जो कि घटना की उत्पत्ति है। अ.सा.-4 की जांच के संदर्भ में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का समर्थन नहीं किया गया कि उस पर "बलात्कार" जैसी घटना हुई थी। यहां तक कि पीड़िता ने भी कहा कि घटना के दौरान उसे कोई चोट नहीं लगी। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि मकान के मालिक शिव प्रसाद चौरसिया, जिनसे अ.सा.-7 के रूप में पूछताछ की गई थी, अपने बयान से मुकर गए और घटना का समर्थन नहीं किया। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण पर , उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने अ.सा.-2 और अ.सा.-3 के परिवार को अपने समारोह में आमंत्रित नहीं किया था और इसलिए, घटना के स्थान पर

पीड़िता की उपस्थिति कथित तिथि और समय पर संदिग्ध प्रतीत होती है। इस गवाह का बयान विरोधाभासी होने के बावजूद, इस मामले में प्रासंगिक प्रतीत होता है ताकि पीड़िता /अ.सा.-1 की गवाही की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सके, जो कि संबंधित अपराध का एकमात्र गवाह है।

27. अ.सा.-5 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच के दौरान उसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या पेन-ड्राइव एकत्र नहीं किया गया था। हालाँकि, अ.सा.-2 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि घटना का वीडियो लेने वाला पेन ड्राइव उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि पेन-ड्राइव, जो कि द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है और अ.सा.-2 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया प्रतीत होता है, को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत अनिवार्य रूप से कोई प्रमाण पत्र के बिना साक्ष्य के रूप में पढ़ा गया था। हालाँकि, वीडियो की उक्त सामग्री के आधार पर, जिसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, कुछ आपत्तिजनक अभियुक्त/अपीलकर्ता से प्रश्न पूछे गए, जहाँ अपीलकर्ता ने उत्तर दिया कि इस अपराध का पीड़िता वीडियो में दिखाई दे रहा है और वह उसमें भी दिखाई देता है, लेकिन उक्त बयान किसी प्रत्यक्ष कृत्य का सुझाव नहीं दे रहा है और केवल अपीलकर्ता की पीड़िता के साथ वीडियो में मौजूदगी यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसके साथ कोई प्रवेशी यौन हमला किया गया था, जैसा कि आरोप लगाया गया था।

28. इस संदर्भ में, तथ्यों की बेहतर समझ के लिए विवादित निर्णय के पैरा-28 और 29 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैंः-

"28. अभियोजन पक्ष के मौखिक साक्ष्य पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अभियुक्त के बयान को इंगित करना प्रासंगिक है जो दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया है. अभियुक्त का बयान दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत पहली बार दिनांक 21.01.2023 को दर्ज किया गया था। इस समय अभियुक्त ने घटना से इनकार किया है और अपने बचाव में कहा है कि भूमि विवाद है लेकिन वीडियो के बाद जो रिकॉर्ड में है उसे अभियुक्त को दिनांक 22.03.2023 को समझाया गया है तो अभियुक्त ने मांग किया है कि वह वीडियो देखना चाहता है तो वीडियो उसे पीठासीन. अधिकारी. कक्ष में दिखाया गया है जहाँ प्रश्न संख्या 14 में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह वही लड़की जो पीड़िता है और प्रश्न संख्या में 16 उसने स्वीकार किया है कि वह वीडियो में पीड़िता के अलावा दूसरा व्यक्ति है, इस समय, अभियुक्त के इस स्वीकारोक्ति से, अभियोजन पक्ष के पक्ष में प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रदान किया गया है, क्योंकि बचाव पक्ष को यह दिखाना आवश्यक था कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं किया है, लेकिन अभियुक्त ने वीडियो में उसकी उपस्थिति स्वीकार किया यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत है कि अभियुक्त पीड़िता पर यौन उत्पीड़न/बलात्कार करने का दोषी है।

29. बचाव पक्ष के वकील ने पेन-ड्राइव के मुद्दे पर दलील दी है कि यह अप्राप्य सामग्री है जिसे सबूत में नहीं लिया जा सकता है। इस पर यह कानून की स्थिति है कि इस निर्णय में, मैंने निष्कर्ष देने के लिए पूरी तरह से साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया है क्योंकि यह अभियुक्त का दं.प्र.सं. के धारा 313 के तहत स्वीकारोक्ति है जो कि फैसले की चर्चा का आधार है न कि वीडियो। "

29. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, जिसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, प्रश्न का आधार नहीं हो सकता है, जिसे दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 313 (1) (बी) के तहत अभियुक्त/अपीलकर्ता के सामने रखा जा सकता है।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी प्रतिवेदन के पैरा-21 और 22 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो **रविन्द्र सिंह केस (उपरोक्त)** के माध्यम से उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं:-

> *"**21.** अंत में, इस अपील ने कानून का एक महत्वपूर्ण ठोस सवाल भी उठाया कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कॉल रिकॉर्ड साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ए और 65-बी के तहत स्वीकार्य होंगे, इस तथ्य को देखते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रमाणन की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है जैसा कि अधिनियम के तहत विचार किया गया है। इस बात की अनिश्चितता कि क्या अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014) 10 एससीसी 473: कानून के इस क्षेत्र में दायर किया गया है या शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 2 एससीसी 801: इस संबंध में सही कानून निर्धारित करता है, अब इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14-7-2020 को अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल (2020) 7 एससीसी में दिए गए निर्णय द्वारा निर्णायक रूप से तय कर दी गई है।*
>
> 1:जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः
>
> > *"61. इसलिए, हम दोहराना चाहेंगे कि धारा 65-बी(4) के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व शर्त है,जैसा कि अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473 में सही ढंग से कहा गया है, और शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2018) 2 एससीसी 801 में गलत तरीके से "स्पष्ट" किया गया है। इस तरह के प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य संभवतः पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि धारा 65-बी (4) कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है। वास्तव में, टेलर बनाम टेलर, (1875) एल. आर. 1 सीएच. डी. 426 में पवित्र सिद्धांत, जिसका इस न्यायालय के कई निर्णयों में पालन किया गया है, को भी लागू किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी(4) में स्पष्ट रूप*

से कहा गया है कि द्वितीयक साक्ष्य तभी स्वीकार्य है जब उसे बताए गए तरीके से प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा नहीं। अन्यथा मानने पर धारा 65-बी(4) निरर्थक हो जाएगी।

*****

73.1.अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473:जैसा कि हमने यहाँ ऊपर स्पष्ट किया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी पर इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है। टोमासो ब्रूनो बनाम यू. पी. राज्य, (2015) 7 एस. सी. सी. 178 में निर्णय, न्यायालय के अनुसार, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा, शफी मोहम्मद बनाम एच. पी. राज्य, (2018) 2 एस. सी. सी. 801 में निर्णय और शफी मोहम्मद बनाम एच. पी. राज्य (2018) 5 एस. सी. सी. 311 के रूप में प्रतिवेदित किया गया दिनांकित 3-4 -2018 निर्णय, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और इसलिए खारिज कर दिया जाता है।

73.2.उपर्युक्त स्पष्टीकरण यह है कि यदि मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाता है, तो धारा 65-बी(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाणपत्र अनावश्यक है। यह लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि मोबाइल फोन, के स्वामी द्वारा भी गवाह बॉक्स में प्रवेश करके और यह साबित करके कि संबंधित उपकरण, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की गई है, उसके स्वामित्व में है और/या उसके द्वारा संचालित है। ऐसे मामलों में जहां "कंप्यूटर" एक "कंप्यूटर प्रणाली" या "कंप्यूटर नेटवर्क" का हिस्सा होता है और ऐसी प्रणाली या नेटवर्क को भौतिक रूप से न्यायालय में लाना असंभव हो जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी प्रदान करने का एकमात्र साधन धारा 65-बी (1) के अनुसार, धारा 65-बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ हो सकता है। "

22. उपरोक्त के आलोक में, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क़ानून के अनुसार होना चाहिए था और प्रमाणन आवश्यकता का पालन करना चाहिए था, ताकि यह अदालत में स्वीकार्य हो। जैसा कि ठीक ही ऊपर कहा गया है, ऐसे प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य, जैसा कि वर्तमान मामले में है, संभवतः

पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि धारा 65-बी (4) कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है। "

31. पीड़िता /अ.सा.-1, जो प्राथमिकीकर्ता हैं, ने कहा कि इस घटना को सूरज कुमार ने देखा था, जिसने अपने मोबाइल से घटना का वीडियो दर्ज किया और उसके बाद इसे सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जो वायरल हो जाता है। प्राथमिकी से यह भी प्रतीत नहीं होता है कि किसने पीड़िता के पिता /अ.सा.-2 को वायरल वीडियो दिखाया है, जबकि पीड़िता ने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत अपने बयान में, जो कि प्राथमिकी दर्ज करने के ठीक दो दिन बाद दिनांक 19.07.2021 को दर्ज किया गया था में स्पष्ट रूप से कहा था कि वीडियोग्राफी अपीलकर्ता की चाची मंजू देवी द्वारा की गई थी और इसे केवल उन्हीं ने फ़ेसबुक पर अपलोड किया था। अपीलकर्ता की माँ ने भी इस खबर को समाज में फैलाया था। एक बार फिर, जब उन्होंने 14 जुलाई, 2022 को अदालत के समक्ष अ.सा.-1, के रूप में गवाही दी, तो उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि यह सह-आरोपी सूरज कुमार थे, जिन्होंने घटना का वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। उसने घटना के दौरान सह-आरोपी सूरज कुमार की उपस्थिति पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के समय कोई तीसरा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। उसे काजल देवी नामक व्यक्ति द्वारा छत पर भेजा गया था, जिसकी अनुसंधान के दौरान या मुकदमे के दौरान भी जाँच नहीं की गई थी।

32. अ.सा.-2 के बयान से यह भी प्रतीत होता है कि वायरल वीडियो को उसके साथ सुरक्षित हिरासत में रखा गया था और अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, लेकिन, अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह, जिनकी बाद में जाँच की गई, से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसे अदालत के समक्ष पेश

किया गया था। यह अपीलाधीन न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि कैसे और किसके द्वारा पेन-ड्राइव, जो वर्तमान प्राथमिकी का स्रोत है अदालत के समक्ष पेश किया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता /दोषी से पूछताछ करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया था। घटना के डेढ़ महीने बाद प्राथमिकी करने में देरी भी घटना को संदिग्ध मानने का एक महत्वपूर्ण कारण है, केवल धमकी देना इस देरी का ठोस कारण नहीं लगता।

33. उपरोक्त चर्चा किए गए ऐसे सभी तथ्यों ने इस अदालत को पीड़िता की गवाही पर विश्वास न करने के लिए बाध्य किया, क्योंकि वह "उत्कृष्ट गवाह" के परीक्षण के योग्य थी। ,जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आरोप का मूल पहलू, पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत उपलब्ध अनुमान को प्रमाणित करता प्रतीत होता है, विशेष रूप से, अ.सा.-7 के बयान की पृष्ठभूमि में, जो परिसर का मालिक है, ने पीड़िता और उसके पिता को दिनांक 30.05.2021 को अपनी बेटी प्रियंका की शादी के अवसर पर किसी भी निमंत्रण से इनकार कर दिया, जहाँ कथित घटना लगभग रात 11:30 बजे हुई थी।

34. इसलिए, अपील स्वीकार की जाती है।

35. तदनुसार, विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-VI-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा पारित दिनांक 01.05.2023 की दोषसिद्धि और दिनांक 16.05.2023 की सजा का आदेश, 2023 विचारण संख्या 142, 2022, का आर. एन. 22 में जो 2021 के महिला थाना कांड संख्या 50 से उत्पन्न हुआ, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और अपास्त किया जाता है।

36. परिणामस्वरूप, उपरोक्त नामित अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

37. जमा किया गया जुर्माना, यदि कोई हो, अपीलकर्ता को तुरंत वापस कर दिया जाए।

38. कार्यालय को इस फैसले की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय अभिलेखों को तुरंत विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।